www.adbhutsamachar.com

अद्भुत समाचार

वर्ष – 15 | अंक–49 | RNI-No.: UPHIN/2011/43806 | लखनऊ,शनिवार 17 जनवरी, 2026 | प्रातः कालीन संस्करण | (हिन्दी दैनिक) | पृष्ठ–4 | मूल्य 1 रुपया

विश्वविद्यालय एक खेल गोद लें खेलों से निखरेगा युवा और साकार होगा विकसित भारत :मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर, 16 जनवरी (एजेंसी) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को चाहिए कि वे किसी एक खेल को गोद लेकर उससे जुड़ी प्रतिभाओं को निखारें। खेलों के माध्यम से युवाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनुशासन और खेल भावना का विकास होगा, जिससे वे नशे और सामाजिक विकृतियों से दूर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा खेलेगा तो खिलेगा और यही सशक्त युवा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।मुख्यमंत्री दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता के औपचारिक उद्घाटन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह चरित्र निर्माण, आत्मअनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सशक्त जरिया हैं। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देकर ही स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश खेलों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में स्थापित की जा चुकी है और मेरठ आज खेल सामग्री निर्माण का प्रमुख केंद्र बन चुका है, जिसे सरकार ने ओडीओपी योजना से जोड़ा है। इससे युवाओं को खेल के साथ रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीते 11 वर्षों में देश में एक नई खेल संस्कृति का विकास हुआ है। वर्ष 2014 से पहले खेल और खिलाड़ियों की उपेक्षा होती थी, जबकि आज खेलो इंडिया, फिट इंडिया और सांसद खेल प्रतियोगिता जैसे अभियानों ने गांव–गांव तक प्रतिभाओं को पहचान और मंच दिया है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि ऋषि परंपरा का उद्घोष 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' आज भी उतना ही प्रासंगिक है। स्वस्थ शरीर से ही जीवन के सभी साधन प्राप्त किए जा सकते हैं। खेलों से जुड़कर नियम, संयम और अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। उन्होंने संतोष जताया कि आज समाज में बेटा–बेटी के बीच भेदभाव कम हो रहा है और अभिभावक बच्चों की खेल प्रतिभा को पूरे मन से प्रोत्साहित कर रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया है। हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान और ओपन जिम, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम तथा जिला स्तर पर स्टेडियमों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। खेलों को जन–जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 96 हजार से अधिक युवक मंगल दलों और महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट वितरित की गई हैं। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने आकर्षक पुरस्कार और सम्मान की व्यवस्था की है। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता दी जाती है और पदक विजेताओं को करोड़ों रुपये के पुरस्कार के साथ सरकारी नौकरी प्रदान की जाती है। अब तक 500 से अधिक पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी सेवा में नियुक्त किया जा चुका है।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए अभी से अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी करनी होगी। उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरा पर देश के 14 राज्यों से आई महिला बास्केटबॉल खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि गोरखपुर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध है। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री ने बास्केटबॉल कोर्ट में फीता काटकर और बॉल उछालकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया तथा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया।

भारतीय युवा स्टार्टअप्स में नए रिकार्ड बना रहे हैं: पीएम मोदी

नयी दिल्ली, 16 जनवरी (एजेंसी) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर देश के स्टार्टअप समुदाय को बधाई दी और कहा कि भारतीय युवा स्टार्टअप्स में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं।श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह दिन भारतीयों, खासकर युवाओं के 'साहस, नवाचार की भावना और उद्यमशीलता के जोश' का जश्न मनाने का दिन है। उन्होंने युवाओं को वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की तरक्की का श्रेय दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा, ष्अपने पक्के इरादे और लगन से हमारे युवा दोस्त स्टार्टअप की दुनिया में लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। उनका जोश और जुनून विकसित भारत के सपने को साकार करने में सबसे बड़ी ताकत बनेगा।ष उन्होंने लगन के महत्व को बताते हुए एक संस्कृत श्लोक भी उद्धृत किया, जिसमें कहा गया है कि लगातार कोशिशों से सबसे मुश्किल काम भी पूरे किए जा सकते हैं, जैसे पानी की लगातार बूंदें समय के साथ चट्टान को भी घिस देती हैं।गौरतलब है कि पिछले एक दशक में भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में से एक के रूप में उभरा है, जिसमें दिसंबर 2025 तक दो लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) जैसे प्रमुख केंद्रों ने इस बदलाव का नेतृत्व किया है, घरेलू और वैश्विक निवेश को आकर्षित किया है। फिनटेक और हेल्थ टेक से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) तक के क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया है। सरकार ने वर्ष 2016 में शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम ने नियामक बोझ को कम करने, पूंजी तक पहुंच में सुधार करने और उद्यमियों के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें युवा–नेतृत्व वाले नवाचार पर विशेष जोर दिया गया है।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महाविजय के बाद बीजेपी का विपक्ष पर हमला, सुधांशु त्रिवेदी बोले-इंडिया गठबंधन का अस्तित्व खत्म

मुंबई 16 जनवरी (एजेंसी)महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन की बड़ी जीत पर पार्टी की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है।उन्होंने कहा कि इन नतीजों ने साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र की जनता ने नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी खेमे की कमजोरी पर तंज कसते हुए पूछा, क्या अब इंडिया गठबंधन का कोई वजूद बचा भी है? उन्होंने तर्क दिया कि केरल, दिल्ली और अब महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में यह गठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है। त्रिवेदी के अनुसार, जनता अब केवल विकास और स्थिरता के एजेंडे को चुन रही है जिसे महायुति सरकार ने जमीन पर उतारा है। भाजपा नेता ने इस जीत का श्रेय खास तौर से जेन–जी यानी पहली बार वोट देने वाले युवाओं को दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और राज्य सरकार के विजन पर भरोसा जताया है। त्रिवेदी ने दावा किया कि युवाओं का बीजेपी के पक्ष में आना इस बात का प्रमाण है कि नई पीढ़ी विकसित भारत के संकल्प के साथ मजबूती से खड़ी है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, संसदीय जांच समिति के गठन को दी थी चुनौती

नयी दिल्ली, 16 जनवरी (एजेंसी)सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की ओर से दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत जांच समिति गठित करने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। यह निर्णय न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनाया। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर बेहिसाब नकदी मिलने के बाद उनके खिलाफ शुरू किए गए महाभियोग प्रस्ताव के संबंध में यह समिति गठित की गई थी। न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और लोकसभा सचिवालय का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद आठ जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। न्यायमूर्ति वर्मा ने जांच समिति के गठन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि महाभियोग नोटिस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक ही दिन (21 जुलाई) पेश किए गए थे, फिर भी लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा सभापति के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना या अनिवार्य संयुक्त परामर्श किए बिना एकतरफा रूप से समिति का गठन कर दिया। याचिका में तर्क दिया गया कि अपनाई गई प्रक्रिया न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3(2) के विपरीत थी।

इसमें धारा 3(2) के प्रावधान का हवाला दिया गया, जो यह निर्धारित करता है कि जहाँ संसद के दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्ताव के नोटिस दिए जाते हैं, वहाँ कोई समिति तब तक गठित नहीं की जाएगी जब तक कि प्रस्ताव दोनों सदनों में स्वीकार न कर लिया जाए और यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि 21 जुलाई, 2025 को संसद के दोनों सदनों में न्यायमूर्ति वर्मा के महाभियोग की मांग करने वाले अलग–अलग प्रस्ताव पेश किए गए थे। उसी दिन, तत्कालीन राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद, 11 अगस्त को राज्यसभा के उपसभापति ने उच्च सदन में पेश किए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। एक दिन बाद, 12 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. एम. श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य की सदस्यता वाली एक जांच समिति के गठन की घोषणा की। सुनवाई के दौरान रोहतगी ने तर्क दिया कि चूंकि प्रस्ताव दोनों सदनों में एक साथ पेश किए गए थे, इसलिए जांच समिति केवल अध्यक्ष और सभापति द्वारा संयुक्त रूप से गठित की जा सकती थी। उपसभापति के पास राज्यसभा के प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार नहीं था। सॉलिसिटर जनरल ने हालांकि दलील दी कि समिति का गठन राज्यसभा के प्रस्ताव के खारिज होने के बाद ही किया गया था। पीठ ने टिप्पणी की कि उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम थे। अदालत ने यह भी सवाल किया कि यदि समिति के गठन में कोई प्रक्रियात्मक कमी मान भी ली जाए, तो इससे न्यायमूर्ति वर्मा को किस तरह का नुकसान हुआ है। निर्णय के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होने के बाद और अधिक जानकारी मिल सकेगी।

पंजाब राजनीति में बीजेपी का बड़ा दांव

दिग्गज नेता जगमीत सिंह ने समर्थकों संग थामा कमल

67 वर्षीय जगमीत बराड़ के अलावा, उनके भाई रिपजीत सिंह बराड़ (पूर्व विधायक), ओंकार सिंह सिद्धू (पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पूर्व ओएसडी) और चरणजीत सिंह बराड़ (एसएडी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के पूर्व ओएसडी) भी भाजपा में शामिल हो गए हैं।

नयी दिल्ली, 16 जनवरी (एजेंसी)आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की उपस्थिति में प्रमुख नेता जगमीत सिंह बराड़, उनके भाई और पूर्व विधायक रिपजीत सिंह बराड़, पूर्व ओएसडी चरणजीत सिंह बराड़ और पूर्व ओएसडी ओंकार सिंह भाजपा में शामिल हो गए। इस अवसर पर पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, कार्यवाहक अध्यक्ष अश्वनी शर्मा और विनीत जोशी भी उपस्थित थे। 67 वर्षीय जगमीत बराड़ के अलावा, उनके भाई रिपजीत सिंह बराड़ (पूर्व विधायक), ओंकार सिंह सिद्धू (पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पूर्व ओएसडी) और चरणजीत सिंह बराड़ (एसएडी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के पूर्व ओएसडी) भी भाजपा में शामिल हो गए हैं।जगमीत बराड़ ने 2015 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिससे पार्टी के साथ उनका तीन दशक से अधिक पुराना नाता टूट गया था। उन्होंने 2016 में लोक हित अभियान नामक अपनी पार्टी शुरू की थी। वह 2016 में ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और पार्टी छोड़ने से पहले 2018 तक इसकी राज्य इकाई के अध्यक्ष रहे। जगमीत वर्ष 2019 में शिरोमणि अकाली दल में भी शामिल हुए थे। दिसंबर 2022 में, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता के रूप में उन्होंने घोषणा की थी कि उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा के पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़, पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भाजपा में शामिल हुए नेताओं का स्वागत किया। सैनी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि पंजाब के लोगों ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा, "सभी वर्ग इस सरकार से परेशान हैं। भाजपा पंजाब में अगली सरकार बनाएगी। लोगों ने अपना मन बना लिया है।भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए सैनी ने कहा आम लोगों, व्यापारियों और अन्य वर्गों में डर का माहौल है। जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उनके परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। राज्य में भय का वातावरण बना हुआ है।" सैनी ने कहा कि यदि कोई पंजाब को आगे ले जा सकता है तो वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ही है। हरियाणा का हवाला देते हुए उन्होंने किसानों सहित विभिन्न वर्गों के लिए भाजपा सरकार द्वारा उठाए गए कई कल्याणकारी कदमों का जिक्र किया और कहा कि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विपरीत अपने वादों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस शासन के दौरान जो कुछ हुआ उसे देखा और पार्टी अपने वादे पूरे करने में विफल रही। लोगों ने आप को मौका दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह भी कांग्रेस के रास्ते पर ही चलेगी। जाखड़ ने भी आप सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पंजाब में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, "लोग भाजपा को बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं, लोग मजबूत नेतृत्व चाहते हैं।

ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, बोलीं, बंगाल में अल्पसंख्यक वोटरों को बनाया जा रहा निशाना

कोलकाता, 16 जनवरी (एजेंसी) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग (ईसीआई) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को जानबूझकर मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि अल्पसंख्यक बहुल मालदा जिले में करीब 90 हजार वोटरों के नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाए जाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायत पूरी तरह जायज है, क्योंकि सबसे ज्यादा निशाना उन्हीं के वोटरों को बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, बल्कि मतुआ, राजवंशी और आदिवासी जैसे पिछड़े वर्गों के वोटरों को भी इस प्रक्रिया में परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि मशहूर हस्तियों तक के नाम सूची से हटाने की बात सामने आ रही है। ममता बनर्जी के अनुसार, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और प्रसिद्ध कवि जय गोस्वामी जैसे लोगों के नाम भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी शुक्रवार को उत्तर बंगाल रवाना होने से पहले यह बयान दे रही थीं। वह दार्जिलिंग जिले के माटीगाड़ा–नक्सलबाड़ी इलाके में महाकाल मंदिर का उद्घाटन करने वाली हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में चल रहे तनाव पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। यह तनाव एक प्रवासी मजदूर के शव के लौटने के बाद शुरू हुआ है, जिसकी कथित तौर पर झारखंड में हत्या कर दी गई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि बेलडांगा में लोगों को भड़काने के पीछे कौन है, यह सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जानबूझकर हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है और इसके पीछे भाजपा का हाथ है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में केंद्रीय एजेंसियों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को भाजपा शासित राज्यों में खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और वहां उनकी हत्याएं तक हो रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार ऐसे मामलों पर नजर रखे हुए है और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।

महाराष्ट्र में फिर चला मोदी मैजिक

नगर निगम चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बोले फड़णवीस

महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को श्रेय दिया है। गठबंधन ने मुंबई बीएमसी सहित 29 में से 24 निगमों में बढ़त हासिल कर ली है, जिसे विकास के एजेंडे पर जनता का विश्वास माना जा रहा है।

नयी दिल्ली, 16 जनवरी (एजेंसी)महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा, फडणवीस ने जीत का श्रेय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया।फडणवीस ने ग पर लिखा कि 2025–26 के नगर निगम चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया! माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमितभाई शाह, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जी के मार्गदर्शन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विधायक रविंद्र चव्हाण तथा सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से भाजपा ने राज्य में एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल की है।फडणवीस के अनुसार, यह जीत प्रगति और विकास सुनिश्चित करने के भाजपा के दृष्टिकोण में जनता के विश्वास को दर्शाती है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन देने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्वीकार किया है। शिंदे ने कहा कि जनादेश भ्रष्टाचार पर विकास की स्पष्ट प्राथमिकता को दर्शाता है और उन्होंने कहा कि अब मुंबई में एक ष्ट्रि–इंजन सरकारष होगी जो शहर के विकास की दिशा में काम करेगी।शुक्रवार सुबह मतगणना शुरू होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के महायुति गठबंधन ने मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई और नागपुर सहित 29 नगर निगमों में से 24 में बढ़त हासिल कर ली है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में रुझान के अनुसार भाजपा और शिवसेना का गठबंधन 227 वार्डों में से 116 में आगे चल रहा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिन्होंने गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा था, अधिकांश जिलों में पिछड़ रही हैं। रुझानों के अनुसार, महायुति गठबंधन ने बीएमसी में सत्ता हासिल करने के लिए आवश्यक 114 बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है।

राहुल गांधी के मिटने वाली स्याही वाले बयान पर बीजेपी का तीखा हमला

कहा- हार के लिए दूसरों को दोष देना राहुल गांधी की पुरानी आदत

मुंबई 16 जनवरी (एजेंसी)महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों के बीच मिटने वाली स्याही को लेकर शुरू हुए विवाद ने अब बड़े राजनीतिक वाकयुद्ध का रूप ले लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोट चोरी और नागरिकों को गुमराह करने के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने करारा जवाब दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के बयान इस बात का साफ संकेत हैं कि कांग्रेस एक बड़ी हार की ओर बढ़ रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब भी चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं होते, वे संस्थाओं पर दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं। भंडारी ने कहा, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वोट चोरी को राष्ट्रविरोधी कृत्य बताया है। असल में जब भी वे हारते हैं कभी ईवीएम, कभी चुनाव आयोग तो कभी स्याही को जिम्मेदार ठहराते हैं। जनता ने उन्हें बार–बार नकारा है क्योंकि वे उन्हें एक गैर–जिम्मेदार नेता के रूप में देखते हैं। एक अन्य भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अब सिर्फ जिद्दी नहीं, बल्कि जिद का साक्षात रूप बन चुके हैं। उनकी बातों का कोई सिर–पैर नहीं होता। कभी स्याही कमजोर है, कभी वोट चोरी हो रहे हैंवे अपनी कमियां देखने के बजाय हर बार नए बहाने गढ़ते हैं। जनता ने उन्हें और उनकी पार्टी को पूरी तरह खारिज कर दिया है। दरअसल, महाराष्ट्र निकाय चुनाव के दौरान कई मतदाताओं ने दावा किया था कि मतदान के बाद लगाई गई अमिट स्याही आसानी से मिट रही है। राहुल गांधी ने इस खबर को साझा करते हुए एक्स पर लिखा था, चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को गुमराह करना लोकतंत्र में भरोसे को खत्म करने जैसा है। वोट चोरी एक राष्ट्रविरोधी कृत्य है। इस बीच, दोपहर तक के रुझानों में भाजपा–शिवसेना गठबंधन (महायुति) महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों में बढ़त बनाए हुए है।

गठबंधन से दूर ही रहेंगी मायावती

गठबंधन की राजनीति के कई सियासी रंग दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग जब 16 जनवरी को खिचड़ी खाकर और खिचड़ी का दान कर मकर संक्रांति मना रहे थे, उसी समय बसपा प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपना जन्मदिन मना रही थीं। मायावती ने इस अवसर पर गठबंधन को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दिया। उन्होंने कहा कि जब बसपा को भरोसा होगा कि गठबंधन करने वाली पार्टी अपना वोट बसपा को ट्रांसफर कराएगी, तभी गठबंधन के बारे में सोचेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए मायावती ने कहा कि अभी गठबंधन की कोई जल्दबाजी नहीं है।

इस प्रकार बसपा प्रमुख ने पक्ष और विपक्ष के सभी दलों को बता दिया कि उन्हें किसी से परहेज नहीं है। सवाल सिर्फ वोटों का है। गिव एण्ड टेक की तर्ज पर ही बसपा गठबंधन करेगी। यूपी में चार बार सरकार बना चुकीं मायावती ने दूसरे दलों के बारे में अपना नजरिया भी बताया। अपने जन्मदिन के अवसर पर मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने बसपा के मूवमेंट को रोकने का ही सदैव प्रयास किया है। इसी प्रकार सपा को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडागर्दी चरम पर रहती थी। उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस हमले की याद भी दिलाई। इस प्रकार मायावती ने तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों की आलोचना की लेकिन एक चुनावी पांसा भी फेंका। अभी हाल में ब्राह्मण विधायकों की बैठक का विशेष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति हमदर्दी दिखाई। यहां पर ध्यान देने की बात है कि 2007 में ब्राह्मणों के समर्थन से ही बसपा की स्वतंत्र रूप से सरकार बनी थी। उसी समय यह नारा लगा था कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मायावती मुस्लिम वोट बैंक को भी सहेजना चाहती हैं, इसीलिए बिहार में महिला डाक्टर का हिजाब उठाने पर नाराजगी जतायी थी।

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने 16 जनवरी को अपने जन्मदिन पर पार्टी की उपलब्धियों और गठबंधन के बारे में बात की। मायावती ने कॉन्फ्रेंस में गठबंधन को लेकर साफ–साफ कहा कि जब बसपा को भरोसा होगा कि गठबंधन करने वाली पार्टी अपना वोट बसपा को ट्रांसफर कराएगी तब गठबंधन के बारे में सोचेंगे ,अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया कि अभी गठबंधन की कोई जल्दबाजी नहीं है और इसके लिए सही समय का इंतजार किया जाएगा।मायावती ने अपने जन्मदिन पर बात करते हुए कहा, नव वर्ष के पहले महीने में ही आज के दिन पूरे देशभर में बसपा के लोग मेरा जन्मदिन पार्टी व मूवमेंट के हित में इसे जनकल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत सादगी के साथ मनाते हैं। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ लोग आमजन से जुड़ी उन जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश में बसपा की 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार में शुरू किया गया था। हमने उन्हें जमीनी हकीकत में लागू करके दिखाया था, जिससे उत्तर प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ–साथ यहां दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी स्थिति में काफी सुधार आया।

इस अवसर पर मायावती ने ब्राह्मण कार्ड भी खेला। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी बसपा के मूवमेंट को देश में रोकने के लिए तरह–तरह के हथकंडे अपनाती रहती हैं। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि ब्राह्मणों ने अपनी चिंताओं पर स्वाभाविक रूप से चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि बसपा ने हमेशा ब्राह्मणों को उचित सम्मान दिया है और ब्राह्मणों को किसी की चाटुकारिता या बहकावे की जरूरत नहीं है। मायावती ने ब्राह्मणों से अपील की कि वे भाजपा, सपा या कांग्रेस के बहकावे में न आएं। मायावती ने आश्वासन दिया कि यदि बसपा की सरकार बनी तो ब्राह्मणों को पूरा सम्मान मिलेगा, साथ ही क्षत्रियों, जाट समाज, दलितों और अल्पसंख्यकों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। मायावती ने कहा कि बसपा की सरकार में कभी मंदिर, मस्जिद या चर्च नहीं तोड़ा गया। सपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा के शासन में गुंडागर्दी चरम पर रहती थी, उनके ऊपर स्टेट गेस्ट हाउस में हमला हुआ और दलितों पर अत्याचार हुए। वहीं, उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि आम जनता खासकर दलित बहुत परेशान हैं, कानून–व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जनता बसपा सरकार चाहती है। मायावती ने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाते हुए मांग की कि बैलेट पेपर से चुनाव हों। उन्होंने देश में चल रहे एसआईआर के काम में भी गड़बड़ियों की शिकायतों का जिक्र किया।

इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री ने लिखा कि वे प्रभु श्रीराम से मायावती के दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ की कामना करते हैं। बसपा सुप्रीमो 16 जनवरी 2026 को 70 साल की हो गईं। उन्होंने 40 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी। मायावती का जन्म दिल्ली के एक साधारण परिवार में हुआ था और राजनीति में आने से पहले वे एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत थीं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम से प्रभावित होकर वे राजनीति में शामिल हुईं और जल्द ही उनकी मुख्य उत्तराधिकारी बनकर उभरीं।

मायावती ने कुल चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वे भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनीं। उनके 2007 से 2012 के कार्यकाल को विशेष रूप से याद किया जाता है, क्योंकि उस दौरान उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और सोशल इंजीनियरिंग (दलित और प्रशासनिक तौर पर मायावती को एक आयरन लेडी के रूप में देखा जाता है, जो अपनी सख्त कार्यशैली और बेहतरीन कानून–व्यवस्था के लिए जानी जाती थीं। उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे, पार्कों और स्मारकों का निर्माण हुआ, जिनमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर और कांशीराम के सम्मान में बनाए गए विशाल स्थल शामिल हैं। हालांकि, इन स्मारकों पर भारी खर्च को लेकर वे कई बार विवादों और आलोचनाओं के घेरे में भी रहीं। आज भी भारतीय राजनीति में वे करोड़ों वंचितों और दलितों के लिए आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाती हैं। मायावती ने बिहार चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे। मायावती ने कहा कि अगर चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष होते तो बसपा और सीट जरूर जीतती। मालूम हो कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीट में बसपा को मात्र एक सीट पर जीत मिली है। मायावती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला डाक्टर का हिजाब उठाने की भी कड़ी आलोचना की थी। (हिफी)

सम्पादकीय

नवाचार, समावेशन और भारत की प्रगति को गति देते हैं स्टार्टअप

स्टार्टअप इंडिया पहल पूरे देश में एक समग्र और नई सोच वाले इकोसिस्टम के रूप में विकसित हुई है। यह युवाओं की उद्यमशील ऊर्जा को रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को तेज करने की दिशा में लगाकर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के मिशन को साकार करने का मार्ग तैयार कर रही है।

भारत में आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक मौजूद है। आज उद्यमिता एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुकी है, जो भारत के आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दे रही है और विकास व रोजगार सृजन का नया इंजन बन रही है।यह परिवर्तन रातोंरात नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री ने 2016 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की, तब उन्होंने एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी दृष्टि रखी कि उद्यमिता देश के हर जिले और हर ब्लॉक तक पहुंचे।16 जनवरी 2016 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की ओर से शुरू किए जाने के बाद से स्टार्टअप इंडिया ने लंबा सफर तय किया है। स्टार्टअप देश की अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई ऊर्जा भर रहे हैं। आईटी सेवाएं, स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान, शिक्षा, कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। इसके अलावा, जलवायु तकनीक और अवसंरचना सहित 50 से अधिक अन्य उद्योगों में भी नए उद्यम सामने आए हैं। यह व्यापकता विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और मजबूती को दर्शाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

नवाचार और एआईरू पिछले एक दशक में एक बड़ा बदलाव नवाचार और गहन तकनीक पर बढ़ते ध्यान के रूप में देखा गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 2016 में 81वें स्थान से बढ़कर पिछले वर्ष 38वें स्थान पर पहुँच गई है, और गहन तकनीक से जुड़े स्टार्टअप्स को सरकार का समर्थन इसे आगे और बेहतर करेगा। प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल के आधार पर एआई स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

गहन तकनीक वाला राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है, तथा इंडिया एआई मिशन और रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना की शुरुआत की गई है। भारत के स्टार्टअप एयरोनॉटिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा, रोबोटिक्स, हरित तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भी नवाचार कर रहे हैं। बौद्धिक संपदा के निर्माण में तेज वृद्धि इस प्रवृत्ति को और मजबूत करती है। भारतीय स्टार्टअप्स ने 16,400 से अधिक नए पेटेंट आवेदन दाखिल किए हैं, जो मौलिक नवाचार, दीर्घकालिक मूल्य सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है।

अखिल भारतीय विकासरू उद्यमिता को देशभर में मिल रहा समर्थन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2016 में केवल चार राज्यों में स्टार्टअप नीतियां थीं, जबकि आज भारत के 30 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष स्टार्टअप ढांचे मौजूद हैं। अब हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जो संस्थागत समर्थन की मजबूती और जमीनी स्तर की भागीदारी को दर्शाता है।

अब तक 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है, जो नीति–आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के एक दशक के सतत विकास को दर्शाता है। केवल 2025 में ही 49,400 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता मिली, जो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के बाद सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि है।

समावेशन इस पूरी यात्रा की एक मजबूत आधारशिला रहा है। महिला नेतृत्व वाले उद्यम एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं, जहां 45 प्रतिशत से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक है। इसके अलावा, लगभग आधे स्टार्टअप गैर–मेट्रो शहरों में स्थित हैं, जो नवाचार और रोजगार के नए केंद्र के रूप में टियर–2 और टियर–3 शहरों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

लोकल से ग्लोबलरू जैसे–जैसे भारतीय स्टार्टअप्स का विस्तार हो रहा है, पूरी दुनिया उनके लिए बाजार बनती जा रही है। वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया ने मजबूत अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां बनाई हैं। अब 21 अंतरराष्ट्रीय ब्रिज और 2 रणनीतिक गठबंधन मौजूद हैं, जो यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन और इजराइल सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बाजार तक पहुंच, सहयोग और विस्तार को आसान बनाते हैं। इन पहलों से अब तक 850 से अधिक स्टार्टअप्स लाभान्वित हो चुके हैं।

स्वीडन, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और इजराइल की मेरी हालिया यात्राओं में स्टार्टअप्स भारत के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों का अहम हिस्सा रहे। इन प्रयासों ने वैश्विक मंच पर भारतीय नवाचार को प्रदर्शित करने का अवसर दिया, साथ ही हमारे उद्यमियों को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की नवाचार और व्यापारिक कार्यप्रणालियों से परिचित कराया।

सुधार और बाजार तक पहुंचरू इस विकास को संभव बनाने में कारोबार करने में आसानी सुधारना एक मुख्य आधार रहा है। पात्र स्टार्टअप अपने पहले दस वर्षों में से किसी भी तीन लगातार वर्षों के लिए कर अवकाश का लाभ ले सकते हैं। अब तक 4,100 से अधिक स्टार्टअप्स को इसके लिए पात्रता प्रमाणपत्र मिल चुके हैं।60 से अधिक नियामकीय सुधारों के माध्यम से अनुपालन का बोझ कम किया गया है, पूंजी जुटाने को आसान बनाया गया है और घरेलू संस्थागत निवेश को मजबूत किया गया है। एंजेल टैक्स को समाप्त करने और वैकल्पिक निवेश कोषों (एटीएफ) के लिए दीर्घकालिक पूंजी के रास्ते खोलने से स्टार्टअप फंडिंग का पारिस्थितिकी तंत्र और सशक्त हुआ है। बाजार तक पहुंच को प्राथमिकता दी गई है।

डीके को प्रयास से ज्यादा प्रार्थना पर यकीन

Hkkरत जैसे आस्था के देश में भी हर किसी को भाग्य पर भरोसा नहीं होता। उनकी नजर में कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। इसके विपरीत बहुत लोग ऐसे हैं जो कर्म के साथ भाग्य पर भी विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि कर्म ही सब कुछ नहीं है, भाग्य अर्थात् नियति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पिछले दिनों जब कहा कि प्रयास भले ही विफल हो जाए लेकिन प्रार्थना विफल नहीं होती। तो लगा कि उन्हें अब भाग्य पर ज्यादा भरोसा है। डीके शिवकुमार को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था और इसके लिए पिछले कुछ महीनों से डीके और उनके समर्थक प्रयास भी कर रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं रह गया कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है लेकिन राज्य में सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रह चुके सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वे अब भी कह रहे हैं कि वह पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। अब 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन डीके शिवकुमार ने सोशल प्लेटफार्म एक्स पर ऐसा लिख दिया कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गयी है। दरअसल डीके शिवकुमार का यह ट्वीट इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे ठीक पहले उन्होंने मैसूर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी से उसी दिन मुख्यमंत्री सिद्धा रमैया भी मिले थे। सिद्धा रमैया का पक्ष इसलिए भी मजबूत समझा जा रहा है क्योंकि उनकी सरकार ने विज्ञापन बजट से नेशनल हेराल्ड को कथित तौर पर करोड़ों का भुगतान किया है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस पर सवाल भी उठाये हैं।

कर्नाटक में कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ एक संक्षिप्त मुलाकात की है जिसके बाद राज्य में राजनीतिक अटकलों का दौर और तेज हो गया है। उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर एक अहम पोस्ट किया है। प्रयास भले ही विफल हो जाये लेकिन प्रार्थना विफल नहीं होती। राजनीति के जानकार इसे पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर देख रहे हैं। पिछले महीने इस सिलसिले में राहुल गांधी से मिलने की डीके शिवकुमार की सारी कोशिशें नाकाम रही थीं। लेकिन 13 जनवरी को तमिलनाडु से दिल्ली लौटने के रास्ते में मैसुरु एयरपोर्ट पर टारमेक पर ही राहुल गांधी ने पहले डीके शिवकुमार और फिर सीएम सिद्धारमैया से अलग–अलग अकेले में मुलाकात की। डीके शिवकुमार के ट्वीट को देखकर लगता है कि राहुल गांधी ने उन्हें अभी और इंतजार करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में विस्तृत चर्चा के लिए दोनों नेताओं को जल्द ही दिल्ली बुलाने की बात राहुल गांधी ने कही है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में संभावित बदलाव को लेकर जारी अटकलों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आलाकमान जो भी फैसला करेगा वह उस फैसले का पालन करेंगे। हालांकि, सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच जारी खींचतान और सरकार में जारी फेरबदल की चर्चाओं को देखते हुए दोनों की राहुल गांधी के साथ मुलाकात को अहम माना जा रहा है। हवाईअड्डे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से संक्षिप्त मुलाकात के बाद सिद्धरमैया ने कहा कि पार्टी के भीतर नेतृत्व से जुड़े मुद्दों को लेकर कोई भ्रम नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा, आज सुबह कोई चर्चा नहीं हुई और न ही शाम को कोई चर्चा निर्धारित है। वह (राहुल गांधी) तमिलनाडु के गुडालूर जा रहे हैं और दिल्ली वापसी के लिए मैसूर लौटेंगे। मैं उन्हें विदा करने जाऊंगा। नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं से जुड़ी खबरों के बारे में पूछे जाने पर सिद्धरमैया ने कहा, कैसी अटकलें? आप (मीडिया) ही अटकलें लगा रहे हैं। पार्टी के भीतर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। यह सवाल ही बेबुनियाद है।

मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल से जुड़ी अफवाहों पर मुख्यमंत्री ने कहा, किस बात को लेकर भ्रम है? ये सब अखबारों और मीडिया में हो रही चर्चाएं हैं। पार्टी में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के पिछले साल 20 नवंबर को पांच साल के कार्यकाल का आधा पड़ाव पूरा करने के बाद नेतृत्व में संभावित बदलाव की अटकलें तेज हुई हैं।

2023 में कांग्रेस सरकार के गठन के समय सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सत्ता–साझाकरण समझौते की खबरों के चलते नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को हवा मिली है। विधायकों के नेतृत्व परिवर्तन की तारीख बताने से जुड़ी खबरों पर सिद्धारमैया ने कहा, इस मुद्दे पर या तो (उपमुख्यमंत्री) डीके शिवकुमार बोलेंगे या मैं, क्योंकि हम ही इस बारे में जानते हैं। क्या हमने बात की है? नहीं। वास्तव में, विधायक अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं– यह आप (मीडिया) हैं जो इस पर चर्चा कर रहे हैं।

यह पूछे जाने पर कि शिवकुमार और उनके समर्थक सत्ता हस्तांतरण के वादे का जिक्र कर रहे हैं, सिद्धरमैया ने कहा, यह कब कहा गया था? उन्होंने कुछ नहीं कहा आप कहानियां गढ़ रहे हैं।

सिद्धारमैया ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक कारण कर्नाटक सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी के अखबार नेशनल हेराल्ड को कथित तौर पर किसी भी अन्य राष्ट्रीय दैनिक की तुलना में ज्यादा विज्ञापन देना है। चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य में इस अखबार का ना तो कोई सर्कुलेशन है और न ही पाठक संख्या, इसके बावजूद इस अखबार को बड़े राष्ट्रीय दैनिकों से कहीं ज्यादा फंड मिला है।सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य सरकार के विज्ञापन बजट से नेशनल हेराल्ड को कथित तौर पर करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले लगातार दो सालों में कर्नाटक में नेशनल अखबारों के विज्ञापन खर्च में सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा नेशनल हेराल्ड को दिया। साल 2023–24 में नेशनल हेराल्ड को कर्नाटक सरकार ने करीब 1 करोड़ 90 लाख का विज्ञापन दिया जबकि साल 2024–25 में ये राशि 99 लाख थी। साल 2024–25 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय दैनिक अखबारों में विज्ञापन पर कुल 1 करोड़ 42 लाख खर्च किया जिसका करीब 69 फीसदी हिस्सा नेशनल हेराल्ड के खाते में गया।

यह जानकारी सामने आने के बाद विपक्षी दल बीजेपी ने कांग्रेस पर जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम और सीनियर बीजेपी नेता डॉ. सीएन अश्वथ नारायण ने इसे 'करदाताओं के पैसे की खुली लूट' करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस अखबार की राज्य में कोई खास पाठक संख्या नहीं है, उसे सरकारी विज्ञापन क्यों दिए जा रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि बीजेपी को नेशनल हेराल्ड के बजाय संघ की मैगजीन ऑर्गनाइजर की फंडिंग के बारे में सोचना चाहिए। राज्य के वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए सवाल उठाया, 'नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने में क्या गलत है?

पर्यावरण: जान-माल के नुकसान की नेताओं को परवाह नहीं

योगेंद्र योगी

भारत में जलवायु परिवर्तन से सिर्फ मौसम ही नहीं बिगड़ रहा, बल्कि यह बदलाव लोगों की सेहत पर भी सीधा हमला कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए इस अध्ययन के मुताबिक भारत के जलवायु संवेदनशील जिलों में बच्चों के कुपोषित होने का खतरा अन्य जिलों की तुलना में 25 फीसदी अधिक है।

देश के समक्ष पर्यावरण परिवर्तन एक ऐसी चुनौती बन गई है, जिसकी कीमत हर साल हजारों लोगों की जान देकर और अरबों रुपयों के नुकसान से चुकानी पड़ती है। हर साल विकराल होती इस समस्या के नेता और राजनीतिक दल गंभीर दिखाई नहीं देते। वोट बैंक की राजनीति इस गंभीर समस्या पर भारी पड़ रही है। केंद्र और राज्यों की सरकारों के लिए यह समस्या प्राथमिक सूची में नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार साल 2025 के दौरान देश के अलग–अलग हिस्सों में आपदाओं ने भयंकर कोहराम मचाया जिसमें सैकड़ों आम लोगों की जान चली गयी। बीते साल 2025 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश में 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सबसे ज़्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड की गई, जबकि मध्य प्रदेश आपदा से हुई मौतों के मामले में दूसरे नंबर पर रहा। आंधी–तूफान और बिजली गिरने की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें बिहार में रिकॉर्ड की गई। उत्तर–पश्चिम भारत में, विशेषकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में बदल फटने, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसी आपदाओं ने भयंकर कोहराम मचाया। बीते साल 1901 के बाद पिछले 124 साल में से तीसरी सबसे अधिक रिकॉर्ड की गयी।अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनी स्विस रे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत को प्राकृतिक आपदाओं से 12 अरब अमेरिकी डॉलर (एक लाख करोड़ रुपये से अधिक) का नुकसान हुआ। यह 2013–2022 के औसत 8 अरब डॉलर से काफी ज्यादा था। स्विस रे की रिपोर्ट के अनुसार ये बड़े नुकसान उन क्षेत्रों में हुए जहां संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों की संख्या ज्यादा है। इस विश्लेषण में पाया गया कि भारत में पिछले दो दशकों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले कुल वार्षिक नुकसान का लगभग 63 फीसदी हिस्सा बाढ़ से जुड़ा हुआ है। इसका कारण भारत की जलवायु और भौगोलिक स्थिति है।संयुक्त राष्ट्र कार्यालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण की रिपोर्टों के अनुसार भारत प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक आर्थिक नुकसान झेलने वाले शीर्ष देशों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य रिपोर्टों के अनुसार भारत को चरम मौसम की घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल भारी आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन यह आंकड़ा 7 अरब डॉलर से काफी अधिक है, जो हाल के वर्षों में बढ़कर 8.7 अरब डॉलर (2021 की रिपोर्ट के अनुसार) या इससे भी अधिक (जैसे 2023 में 12 अरब डॉलर) हो गया है, क्योंकि बाढ़, तूफान और सूखे जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं। 2003–2012 के दशक के 3.8 अरब डॉलर के औसत से बढ़कर 2013–2022 के दशक में यह औसत 8 अरब डॉलर प्रति वर्ष हो गया है, जो 125: की वृद्धि है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में भारत को जलवायु–संबंधी खतरों से 87 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था।क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 (सीआरआई) की नई रिपोर्ट के अनुसार, 1995दृ2024 की अवधि में भारत दुनिया के उन शीर्ष 10 देशों में रहा है, जिन्हें जलवायु परिवर्तन से जुड़े चरम मौसम–कार्यों (बाढ़, तूफान, हीटवेव, सूखा आदि) का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा है। इस 30–वर्षीय अवधि में भारत में करीब 430 आपदाएं हुईं, जिनमें लगभग 80,000 लोगों की मौत हुई और 1.3 अरब से अधिक लोग प्रभावित हुए। अनुमानित आर्थिक हानि लगभग 170 अरब डालर रही। सीआरआई की रिपोर्ट बताती है कि भारत 'लगातार खतरे' की श्रेणी में आता है। देश में जलवायु आपदाएँ इतनी बार–बार हो रही हैं कि एक घटना के प्रभाव से पूरी तरह उबरने से पहले ही अगली आ जाती है। नहरों, हिमालयी नदियों, समुद्री तटीय इलाकों और कृषि–प्रधान क्षेत्रों के लिए यह विशेष रूप से चिंता की बात है। भारत में जलवायु परिवर्तन से सिर्फ मौसम ही नहीं बिगड़ रहा, बल्कि यह बदलाव लोगों की सेहत पर भी सीधा हमला कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए इस अध्ययन के मुताबिक भारत के जलवायु संवेदनशील जिलों में बच्चों के कुपोषित होने का खतरा अन्य जिलों की तुलना में 25 फीसदी अधिक है। इन जिलों में महिलाओं के घर पर प्रसव और बच्चों के ठिगने होने की आशंका भी अधिक है। मतलब कि जलवायु संकट का सीधा असर मां और शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस कड़ी में दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के शोधकर्ताओं ने अपने एक नए अध्ययन में भारत में जलवायु संकट और स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को उजागर किया है। अध्ययन से पता चला है जलवायु जोखिम वाले जिलों के बच्चों के कुपोषित होने की आशंका 25 फीसदी अधिक है, यानी इन जिलों में बच्चों का वजन उम्र के अनुपात में सामान्य से कम होने का खतरा कहीं ज्यादा है।यूनेस्को की एक नई रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चे अपनी पढ़ाई में डेढ़ साल तक पीछे रह सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़, जंगल की आग, गर्मी और तूफान जैसी आपदाओं ने पिछले 20 सालों में 75: मामलों में स्कूल बंद करवाए हैं। बांग्लादेश, दक्षिण सूडान और भारत जैसे देशों में बच्चे स्कूल नहीं लौट पाते, क्योंकि उनके घर, स्कूल और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। भारत में 16 लाख से ज्यादा स्कूल हैं, जिनमें से कई में न तो पंखे हैं और न ही ठंडक की कोई व्यवस्था। शहरों में, कम आय वाले इलाके खराब शहरी नियोजन और हरियाली की कमी के कारण असमान रूप से प्रभावित होते हैं। ग्रामीण इलाकों और गरीब बस्तियों में स्थिति और खराब है। इन तमाम रिपोर्टों से जाहिर है कि नए साल और आने वाले भविष्य में पर्यावरणीय चुनौतियां और भी गंभीर होंगी। इसकी फिक्र नेताओं और राजनीतिक दलों को नहीं है। उन्हें यदि फिक्र है तो ऐसे तात्कालिक मुद्दों की जिनसे वोट बटोरा जा सके। देश चलाने वालों ने वक्त रहते इन समस्याओं के प्रति यदि गंभीर रुख नहीं अपनाया तो यह हालात देश को भयानक अंधकार की तरफ ले जाने वाले साबित होंगे।

आपरेशन पहचान के तहत लखनऊ में किरायेदार पंजीकरण अभियान तेज, वर्ष 2025 में 13,864 रजिस्ट्रेशन

लखनऊ,संवाददाता। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा जनपद में कानून–व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से 'ऑपरेशन पहचान' के अंतर्गत किरायेदार पंजीकरण अभियान को व्यापक स्तर पर लागू किया गया है। इस अभियान के तहत वर्ष 2025 के दौरान लखनऊ के विभिन्न जोनों में कुल 13,864 किरायेदारों का पंजीकरण किया गया है, जिनका संबंधित थानों की पुलिस टीमों द्वारा लगातार भौतिक सत्यापन भी कराया जा रहा है।पुलिस कमिश्नरेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में मध्य जोन में 843, पूर्वी जोन में 6657, दक्षिणी जोन में 4928, पश्चिमी जोन में 532 तथा उत्तरी जोन में 904 किरायेदारों का पंजीकरण कराया गया। पुलिस का कहना है कि किरायेदारों का समय से पंजीकरण और सत्यापन अपराध नियंत्रण की दिशा में एक प्रभावी कदम है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।मकान मालिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किरायेदार पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बनाया गया है। इसके लिए लखनऊ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट सनबादवूचवसपबम. नच.हवअ.पद और न्च्व्व् ।च्च पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मकान मालिक का यह दायित्व है कि वह अपने यहां रहने वाले किरायेदार की पूरी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से पुलिस को उपलब्ध कराए। यह प्रक्रिया किरायेदार को मकान या संपत्ति किराये पर देने से पहले अथवा अधिकतम एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।पुलिस के अनुसार यदि किसी मकान में एक से अधिक किरायेदार निवास कर रहे हैं, तो सभी का पंजीकरण और सत्यापन कराना आवश्यक है। पंजीकरण के उपरांत संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें मकान मालिकों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की गई है। साथ ही मकान मालिकों को किरायेदार से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और मूल पता अपने पास सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।पुलिस कमिश्नरेट ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि किसी किरायेदार की संलिप्तता आपराधिक गतिविधियों में पाई जाती है और उस किरायेदार की सूचना पहले से पुलिस को नहीं दी गई होती है, तो संबंधित मकान मालिक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा सकती है। वहीं यदि किसी विदेशी नागरिक को मकान किराये पर दिया जाता है, तो मकान मालिक को अनिवार्य रूप से फॉर्म–सी भरकर स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी।ऑपरेशन पहचान को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में लगातार जन–जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस टीमें अपने–अपने क्षेत्रों में मकान मालिकों से संपर्क कर उन्हें किरायेदार पंजीकरण और सत्यापन की अनिवार्यता के बारे में जागरूक कर रही हैं। इसके साथ ही मोहल्लों और आवासीय इलाकों में लाउडस्पीकर के माध्यम से आमजन को भी यह संदेश दिया जा रहा है कि बिना सत्यापन के किरायेदार न रखें और समय से संबंधित जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराएं।पुलिस कमिश्नरेट ने सभी मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने यहां रहने वाले किरायेदारों से चरित्र प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए भी लखनऊ पुलिस की वेबसाइट अथवा न्च्व्व् ।च्च के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। पुलिस का कहना है कि नागरिकों की सहभागिता से ही जनपद में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में "फ्लाई हाई, से नो टू रैगिंग" संदेश के साथ पतंग उड़ान प्रतियोगिता, सौहार्द और सकारात्मकता का दिखा उत्सव

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में "फ्लाई हाई, से नो टू रैगिंग" विषय पर आयोजित पतंग उड़ान प्रतियोगिता का सफल और उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच आपसी सद्भाव, सकारात्मक सोच और रैगिंग के विरुद्ध जागरूकता को मजबूत करना था। प्रतियोगिता के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि स्वस्थ, सुरक्षित और सहयोगपूर्ण शैक्षणिक वातावरण ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का आधार है।कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. राम चंद्रा, प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अमित सिंह, प्रो. नरेन्द्र कुमार तथा आयोजन समिति के संयोजक डॉ. मनोज कुमार डडवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के रचनात्मक और सहभागितापूर्ण आयोजन आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं तथा विश्वविद्यालय परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। उन्होंने कहा कि रैगिंग जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध जागरूकता फैलाना केवल नियमों से नहीं, बल्कि ऐसे सामूहिक आयोजनों से अधिक प्रभावी ढंग से संभव हो पाता है। अतिथियों ने आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे एक सराहनीय और प्रेरक पहल बताया।प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ सहभागिता की। विश्वविद्यालय परिसर में रंग–बिरंगी पतंगें उड़ाते हुए विद्यार्थी हर्षोल्लास के साथ आनंद लेते नजर आए। पूरे कार्यक्रम के दौरान सौहार्द, अनुशासन और आपसी सहयोग का एक सुंदर और प्रेरणादायी दृश्य देखने को मिला, जिसने आयोजन के उद्देश्य को सार्थक किया।कार्यक्रम के दौरान प्रो. एमपी सिंह, पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. सुनील गोरिया, डॉ. राजेश इक्का, डॉ. प्रणव आनंद, डॉ. सुदर्शन चक्रधारी, डॉ. ओपी सैनी सहित अन्य शिक्षक, गैर–शिक्षण कर्मचारी, शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। यह आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण और रैगिंग मुक्त संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया।

हर घर जल योजना के असर की होगी गहन पड़ताल, प्रदेश के 11 मंडलों में इंपैक्ट असेसमेंट, बुंदेलखंड में आईआईटी मद्रास करेगा मूल्यांकन

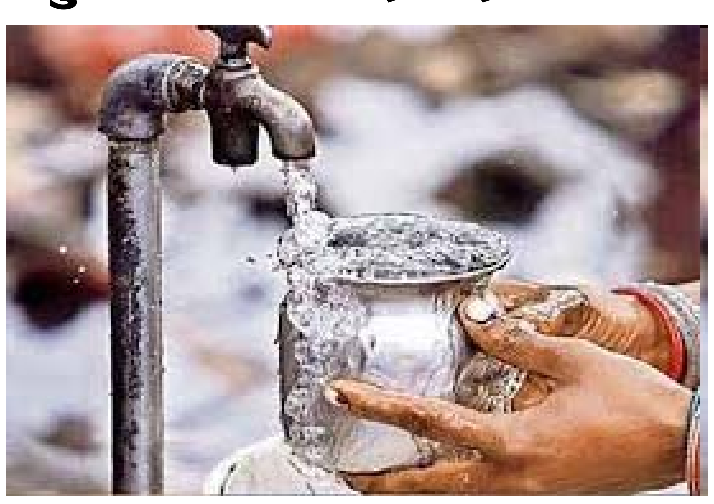

लखनऊ, । जल जीवन मिशन के अंतर्गत लागू 'हर घर जल' योजना ने ग्रामीण जीवन में जिस व्यापक बदलाव की नींव रखी है, उसकी वास्तविक तस्वीर अब वैज्ञानिक और संस्थागत आकलन के जरिए सामने लाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि योजना के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों का प्रभाव आकलन (इंपैक्ट असेसमेंट) केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों, आईआईटी मद्रास तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कराया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह परखा जाएगा कि नल से शुद्ध पेयजल की पहुंच ने ग्रामीण समाज की जीवनशैली को किस हद तक बदला है।वर्तमान में लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी सहित प्रदेश के 11 मंडलों में इंपैक्ट असेसमेंट की प्रक्रिया चल रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को आईआईटी मद्रास को सौंपे जाने की तैयारी है, जबकि मुरादाबाद, आगरा, मेरठ और देवीपाटन मंडलों में केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मूल्यांकन कराने की योजना बनाई गई है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की ओर से इसके लिए संबंधित संस्थाओं को अनुरोध भेजा गया है।नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने के बाद ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य स्तर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। जलजनित बीमारियों में कमी आई है, जिससे परिवारों पर उपचार का बोझ घटा है। बच्चों की शिक्षा में निरंतरता देखने को मिली है, क्योंकि अब उन्हें पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती। रोजगार के लिए होने वाला प्रवासन भी कम हुआ है। सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव महिलाओं के जीवन में देखा गया है, जिन्हें पानी की दैनिक समस्या से मुक्ति मिलने के बाद आत्मनिर्भर बनने और आयवर्धक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिला है। इन सभी पहलुओं का धरातल पर विस्तृत अध्ययन आईआईटी मद्रास की टीम द्वारा किया जाएगा।इससे पहले झांसी और चित्रकूट मंडलों में कराए गए इंपैक्ट असेसमेंट में यह स्पष्ट हुआ था कि नल से जल की सुविधा ने ग्रामीण परिवारों की दिनचर्या को सरल और सुरक्षित बनाया है। गोरखपुर मंडल में हुए अध्ययन में भी शुद्ध पेयजल आपूर्ति के सकारात्मक सामाजिक प्रभाव सामने आए थे। इन्हीं अनुभवों के आधार पर अब बुंदेलखंड के साथ–साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी योजना के प्रभाव को व्यापक स्तर पर परखा जा रहा है। अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडलों में फिलहाल यह प्रक्रिया जारी है।मुरादाबाद, आगरा, मेरठ और देवीपाटन मंडलों में शीघ्र ही प्रभाव आकलन अभियान शुरू करने की तैयारी है। यहां केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के साथ अंतरराष्ट्रीय गैर–सरकारी संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा, ताकि अध्ययन अधिक व्यापक और निष्पक्ष हो सके। जल जीवन मिशन के तहत कराया जा रहा यह इंपैक्ट असेसमेंट यह स्पष्ट करेगा कि नल से आया जल केवल एक सुविधा बनकर रह गया है या वास्तव में ग्रामीण बदलाव की सशक्त धारा बनकर जीवन की दिशा बदल रहा है।

मुंशीपुलिया लखनऊ व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने व्यापारियों को दिलाया भरोसा

लखनऊ। शुक्रवार को मुंशीपुलिया चौराहे पर मुंशीपुलिया लखनऊ व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय और उत्साहपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे। समारोह में बड़ी संख्या में व्यापारी, पदाधिकारी और संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे, जिससे यह आयोजन व्यापारिक एकता और संगठन की मजबूती का प्रतीक बन गया।कार्यक्रम का संचालन अरविन्द पाठक ने किया। उन्होंने मंच से जानकारी देते हुए बताया कि समारोह में लखनऊ व्यापार मंडल के चेयरमैन राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र, कोषाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, युवा अध्यक्ष मनीष गुप्ता सहित अरविन्द पाठक, हिमांशु भट्ट, परमजीत सिंह, अभिषेक सिंह चौहान, मुकेश सिंह, रिंकू यादव, विशाल चौरसिया, बी.बी. सिंह, महेश शर्मा और रवि मिश्रा मंचासीन रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक का अंगवस्त्र, मोमेंटो एवं माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया।इसके उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा मुंशीपुलिया लखनऊ व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नितिन जैन को सौंपी गई, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक गुप्ता और अनुज सिंह बने। कोषाध्यक्ष पद पर एस.पी. मिश्रा तथा उपाध्यक्ष पद पर एस. एस. यादव (एडवोकेट), ओम प्रकाश सिंह, पी.के. श्रीवास्तव, ललित राजपाल, अनिल अग्रवाल, राहुल कुमार जायसवाल और संदीप जायसवाल को दायित्व सौंपा गया। वरिष्ठ संगठन मंत्री आर्क चंदन सिंह, संगठन मंत्री दीपक तिवारी (एडवोकेट) और विनीत जैन बनाए गए। विधि सलाहकार के रूप में सुभाष चंद्रा (एडवोकेट) और अनिल तिवारी (एडवोकेट) को जिम्मेदारी दी गई, जबकि मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन बनाए गए। इसके अलावा रामशंकर गुप्ता, राहुल अग्रवाल, गुलशन कुमार जसवानी, अजित यादव, अनुराग मिश्रा और मोमिन सिद्दीकी को मंत्री एवं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई।समारोह के दौरान अयोध्या रोड क्षेत्र के पवन सिंह और आदर्श प्रताप सिंह को लखनऊ व्यापार मंडल की सदस्यता दिलाई गई। अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र की उपस्थिति में पवन सिंह को उपाध्यक्ष और आदर्श प्रताप सिंह को संगठन मंत्री घोषित किया गया, जिन्हें उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि व्यापार और उद्योग किसी भी समाज की आर्थिक रीढ़ होते हैं। लखनऊ व्यापार मंडल जैसे संगठन व्यापारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उनके समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा, उनकी सुरक्षा और व्यापार को सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि छोटे और मध्यम व्यापारी बिना किसी भय के अपना व्यवसाय कर सकें।लखनऊ व्यापार मंडल के चेयरमैन राजेन्द्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि व्यापार मंडल केवल एक संगठन नहीं, बल्कि व्यापारियों के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा की मजबूत आवाज है। शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से एक सशक्त, जिम्मेदार और समर्पित टीम का गठन हुआ है, जो पूरी निष्ठा से व्यापारियों के हितों की रक्षा करेगीअध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा कि लखनऊ व्यापार मंडल व्यापारियों की एकता, सम्मान और अधिकारों के लिए लगातार संघर्षरत रहा है। समारोह में व्यापारियों की एकजुट भागीदारी यह दर्शाती है कि संगठन दिन–प्रतिदिन और अधिक मजबूत हो रहा है। कोषाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस शपथ ग्रहण समारोह से संगठन को नई ऊर्जा मिली है और नवनियुक्त पदाधिकारी टीम भावना के साथ कार्य करेंगे।इंदिरानगर परिक्षेत्र प्रभारी हिमांशु भट्ट ने बताया कि संगठन का उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र के व्यापारियों को संगठित कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कराना है। उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह चौहान ने संगठन को व्यापारियों की एकजुटता और अधिकारों की मजबूत आवाज बताया, जबकि युवा अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने कहा कि युवा व्यापारियों की भागीदारी से संगठन को नई सोच और नई दिशा मिलती है।अंत में अध्यक्ष नितिन जैन और वरिष्ठ महामंत्री अभिषेक गुप्ता ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा व्यापारियों के हित में निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारियों की उपस्थिति रही, जिससे यह शपथ ग्रहण समारोह व्यापारिक एकता और संगठनात्मक मजबूती का संदेश देता नजर आया।

उत्तर प्रदेश को देश का खाद्य प्रसंस्करण हब बनाने का संकल्प, इंडिया फूड एक्सपो से युवाओं और उद्यमियों को मिलेगा नया मंच :उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण हब बनाया जाना है और इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने युवाओं, किसानों और उद्यमियों से आह्वान किया कि वे इंडिया फूड एक्सपोदृ2026 जैसे आयोजनों का भरपूर लाभ उठाएं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण नीति देश की सबसे बेहतर नीतियों में से एक है और विकसित भारत के प्रधानमंत्री के विजन को हर हाल में पूरा करना हम सभी का संकल्प है।उप मुख्यमंत्री गोमती नगर स्थित रिगेलिया ग्रीन्स में आयोजित तीन दिवसीय इंडिया फूड एक्सपो एवं सेमिनार के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने एक्सपो और प्रदर्शनी का उद्घाटन कर स्टॉलों का अवलोकन किया तथा इंडस्ट्रियल डायरेक्ट्री का विमोचन भी किया। इस अवसर पर पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले डीआरपी, बैंकर्स, उद्यमियों और लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। साथ ही पांच उद्यमियों को एलओसी और सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक भी प्रदान किए गए।सेमिनार को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। उत्पादन, तकनीक, ब्रांडिंग और उपभोक्ताओं के बेहतर जुड़ाव के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है, ताकि भारत को दुनिया की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत है और औद्योगिक निवेश के लिए यहां अनुकूल वातावरण है। युवाओं, उद्यमियों और किसानों के लिए यह समय ऐतिहासिक अवसर लेकर आया है।उन्होंने बताया कि प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण नीति में महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। महिलाओं द्वारा लगाए गए उद्यमों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। स्वच्छ भारतदृस्वस्थ भारत की भावना को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार किए जाने चाहिए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की फसल किसी भी स्थिति में बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। किसान, उद्यमी और उपभोक्ता के बीच एक मजबूत चेन तैयार करनी होगी। इस दिशा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रयासों की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में देश और प्रदेश लंबी छलांग लगा रहे हैं और इंडिया फूड एक्सपो जैसे आयोजन किसानों, उद्यमियों और निवेशकों को एक साझा मंच प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और यहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए असीम संभावनाएं हैं। यह एक्सपो विकसित भारतदृविकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में स्थापित करना है। किसान, युवा, महिला समूह और उद्यमी सभी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। इंडिया फूड एक्सपो निवेश, नवाचार और रोजगार के नए अवसरों का द्वार खोलेगा। प्रदेश सरकार हर निवेशक और उद्यमी के साथ मजबूती से खड़ी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीतिदृ2023 को निवेशकों के अनुकूल बनाया गया है, जिसमें भूमि खरीद, स्टाम्प शुल्क, मंडी शुल्क, बाह्य विकास शुल्क और भूमि उपयोग परिवर्तन में व्यापक छूट दी जा रही है। संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों पर 35 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी, कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन, रीफर वाहन, सोलर ऊर्जा और निर्यात परिवहन पर विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए एकीकृत बाजार क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है।कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बीएल मीना ने उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों और नीति की विस्तृत जानकारी दी। सेमिनार को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल सहित अन्य उद्यमियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक नीरज बोरा, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक टीके शीबू सहित कई उद्यमी, अधिकारी और निवेशक उपस्थित रहे।गौरतलब है कि खाद्य प्रसंस्करण तकनीक तथा खाद्य एवं कृषि उत्पाद उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया फूड एक्सपो एवं सेमिनार का यह दसवां संस्करण 16 से 18 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, मशीन तकनीक और उत्पादों की तीन दिवसीय प्रदर्शनी के साथ–साथ विशेषज्ञों द्वारा उद्योग स्थापित करने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी जा रही हैं।

जोन-6 में अवैध डेयरियों पर नगर निगम का सख्त अभियान, 20 पशु जब्त, विरोध के बीच कार्रवाई

लखनऊ। शहरी स्वच्छता और जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम लखनऊ ने शुक्रवार को जोन–6 के पारा थाना क्षेत्र में अवैध डेयरियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में यह विशेष कार्रवाई की गई, जिसमें पारा थाना क्षेत्र की पिंक सिटी कॉलोनी और सूर्य नगर में संचालित अवैध डेयरियों को निशाने पर लिया गया। कार्रवाई के दौरान डेरी संचालकों द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन प्रशासन ने पूरी सख्ती के साथ अभियान को अंजाम दिया।अभियान के दौरान कुल 11 भैंस, एक पड़िया और आठ गाय जब्त की गईं। जब्त किए गए सभी पशुओं को पीजीआई स्थित कांजी हाउस में निरुद्ध किया गया है, जहां से इन्हें निर्धारित जुर्माना जमा करने के बाद ही छोड़ा जाएगा। यह कार्रवाई स्थानीय नागरिकों की शिकायतों के आधार पर की गई थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि अवैध डेयरियों के संचालक गोबर को खुले प्लॉटों में फेंक रहे हैं और नालियों में बहा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में गंदगी, जलभराव और मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।नगर निगम ने स्पष्ट किया कि नगर निगम अधिनियम 1959 के अंतर्गत शहरी सीमा में भैंस पालन पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि इसे अपदूषण कारक पशु की श्रेणी में रखा गया है। नियमों के अनुसार केवल अधिकतम दो गायों को ही वैध लाइसेंस के तहत पालने की अनुमति है। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से डेयरियों का संचालन किया जा रहा था, जिस पर यह कार्रवाई की गई।इस अभियान में नगर निगम के प्रवर्तन दल के साथ पुलिस बल और पशु कल्याण विभाग की संयुक्त भागीदारी रही। कार्रवाई के दौरान डॉ. अभिनव वर्मा के साथ मनोज, शिवेक, रामकुमार, अभिनव, फुरकान और नदीम ने विशेष सहयोग प्रदान किया। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अवैध डेयरियों के खिलाफ ऐसे अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जोन-1 के कई वार्डों में औचक निरीक्षण, गंदगी और लापरवाही पर सख्त रुख, दोषियों पर जुर्माना व वेतन कटौती के निर्देश

लखनऊ, । वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और लखनऊ जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने महापौर सुषमा खर्कवाल के साथ जोन–1 अंतर्गत विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था, जल निकासी और नगर निगम के कार्यों की जमीनी हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि शहर की साफ–सफाई और बुनियादी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।निरीक्षण की शुरुआत विक्रमादित्य महात्मा गांधी वार्ड स्थित योजना भवन, डायमंड डेरी, उदयगंज से हुई, जहां नालियों की गंदगी और क्षेत्र में फैली अव्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। मौके पर ही तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए गए। सड़क पर मलबा और कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के आदेश भी दिए गए, ताकि स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सके। इसके बाद डायमंड डेरी के पास स्थित पंपिंग स्टेशन के आसपास निरीक्षण किया गया, जहां वर्षों से खाली पड़े एक प्लॉट में जमा मलबे को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए और प्लॉट मालिक के विरुद्ध जुर्माना लगाने के कड़े आदेश जारी किए गए।इसके पश्चात जोन–1 के बाबू बनारसी दास वार्ड में निरीक्षण के दौरान हैदर कैनाल की रिटेनिंग वॉल की मरम्मत कराने और उसके आसपास समुचित साफ–सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। लालकुआं वार्ड में निरीक्षण के दौरान नालियों की सफाई, कूड़े के नियमित उठान और नालियों से होकर गुजर रही पेयजल पाइपलाइन को हटाने पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त पाइपलाइन को शीघ्र स्थानांतरित किया जाए, ताकि स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम समाप्त हों।नजरबाग वार्ड के सुंदरबाग क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान नालियों की सफाई और कूड़ा उठान में लापरवाही पाए जाने पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए जोनल अधिकारी से लेकर अधीनस्थ स्तर तक के अधिकारियों के दो दिन के वेतन की कटौती के निर्देश दिए। जेसी बोस वार्ड में निरीक्षण के दौरान नालियों की समुचित सफाई, क्षेत्र में यूरिनल निर्माण और सीवर की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।पूरे निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेताया कि शहर की स्वच्छता और नागरिक सुविधाएं शासन की प्राथमिकता हैं और इसमें कोताही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के समय नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त सहित नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि कुछ वार्डों में संबंधित पार्षद भी निरीक्षण दल के साथ उपस्थित रहे।

शहरी विकास योजनाओं में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं, परिणाम जमीन पर दिखने चाहिए : ए.के. शर्मा

लखनऊ, । नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने संगम सभागार, लखनऊ में नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शहरी विकास से जुड़ी सभी योजनाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और इनमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं की प्रगति केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसके परिणाम धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन, गौशाला, डॉग शेल्टर, आकांक्षी नगर योजना, वैश्विक नगरोदय योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, सीएम ग्रिड योजना, स्मार्ट पालिका, पंडित दीनदयाल नगरीय विकास योजना सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं में कार्य की गति तेज की जाए और समयबद्ध ढंग से उन्हें पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।आवासीय योजनाओं की प्रगति अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर मंत्री ने असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवासीय योजनाएं आम नागरिकों से सीधे जुड़ी होती हैं, ऐसे में इनमें किसी भी प्रकार की देरी जनहित के विपरीत है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित फाइलें अनावश्यक रूप से लंबित न रखी जाएं। निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाकर योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से जनता तक पहुंचाना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।बैठक में जल निकासी व्यवस्था, झील, तालाब, पोखर, वंदन एवं अंत्येष्टि स्थलों से जुड़े कार्यों में पुनर्विनियोग करने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही कैडर रिव्यू और विभागीय कार्यवाहियों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने इन मामलों में भी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।इस समीक्षा बैठक में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद, सचिव एवं निदेशक नगरीय निकाय अनुज झा, सचिव एवं एमडी जल निगम रविंद्र कुमार प्रथम, विशेष सचिव सूडा एवं जेएमडी जल निगम प्रवीण लक्ष्यकार, विशेष सचिव सत्यप्रकाश पटेल, विशेष सचिव महेंद्र बहादुर सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

शहरी विकास योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, परिणाम धरातल पर दिखे: ए के शर्मा

लखनऊ, । नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने संगम सभागार, लखनऊ में नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि शहरी विकास से जुड़ी सभी योजनाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और इनमें किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान मंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन, गौशाला, डॉग शेल्टर, आकांक्षी नगर योजना, वैश्विक नगरोदय योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, सीएम ग्रिड योजना, स्मार्ट पालिका, पंडित दीनदयाल नगरीय विकास योजना सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों की गति तेज की जाए तथा योजनाओं के परिणाम स्पष्ट रूप से धरातल पर दिखाई देने चाहिए।समीक्षा के दौरान आवासीय योजनाओं की प्रगति अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर मंत्री ने असंतोष व्यक्त किया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवासीय योजनाएं आम नागरिकों से सीधे जुड़ी हैं, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की देरी जनहित के विरुद्ध है। इसके साथ ही सीएम ग्रिड योजना को पालिका स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा सकेगा और नगरों की कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित होगी।मंत्री ए के शर्मा ने यह भी सख्त निर्देश दिए कि आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित फाइलें अनावश्यक रूप से लंबित न रखी जाएं। निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाकर योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से जनता तक पहुंचाना शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक में जल निकासी व्यवस्था, झील, तालाब, पोखर, वंदन एवं अंत्येष्टि स्थलों से जुड़े कार्यों में पुनर्विनियोग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कैडर रिव्यू और विभागीय कार्यवाहियों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा करते हुए इन मामलों में भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।इस समीक्षा बैठक में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद, सचिव एवं निदेशक नगरीय निकाय अनुज झा, सचिव एवं एमडी जल निगम रविंद्र कुमार प्रथम, विशेष सचिव सूडा एवं जेएमडी जल निगम प्रवीण लक्ष्यकार, विशेष सचिव सत्यप्रकाश पटेल, विशेष सचिव महेंद्र बहादुर सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित

नगर में नया जन औषधि केंद्र हुआ प्रारंभ

(सुनील शर्मा)

लखीमपुर खीरी। शहर में एक और जन औषधि केंद्र चालू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार इमली चौराहा से आनंद टाकीज रोड पर मेहता टेंट हाउस के सामने यह

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया है। इधर आसपास में कोई जन औषधि केंद्र नहीं था जिससे लोग अन्य मेडिकल स्टोर पर महंगी दवाएं खरीदते थे। यह जन औषधि केंद्र खुल जाने से गरीब जनता को राहत मिलेगी इस केंद्र में हार्ट, बीपी, शुगर व गैस व अन्य उच्च गुणवत्ता वाली दवाईयाँ सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं।यह केंद्र के मनीष मिश्रा, नीरज शुक्ला, रजत, विनोद, रुची जगदीश आदि ने मिलकर प्रारंभ किया है। इस जन औषधि केंद्र के संचालक नीरज शुक्ला ने बताया कि उन्होंने गरीब जनता को राहत देने के लिए इस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का प्रारंभ किया है जिससे लोग सस्ते रेट में अच्छी औषधीय का लाभ उठा सके।

''धार्मिक असहिष्णुता के मूल में है अज्ञानता --- महात्मा अनिरुद्ध दास जी''

(केके शुक्ला)

लखीमपुरप्रयागराज।सन्त ज्ञानेश्वर स्वामी सदानन्द जी परमहंस द्वारा संस्थापित संस्था सदानन्द तत्त्वज्ञान परिषद के तत्त्वावधान में माघ मेला के शिविर में सत्संग एवं भजन कीर्तन का कार्यक्रम में बोलते हुए महात्मा अनिरुद्ध दास ने कहा— धर्म के नाम पर साम्प्रदायिक तनाव एवं टकराव की जो स्थिति आज समाज में दिखाई पड़ती है, उसका मूल कारण है आध–अधूरे एवं मिथ्या–अक्षम और काल्पनिक ज्ञान पद्धति का लागू किया जाना। अतः जब तक भगवान श्रीविष्णु जी, भगवान श्रीराम जी एवम भगवान श्रीकृष्ण जी वाला ही तत्त्वज्ञान अर्थात 'सम्पूर्ण ज्ञान–विधान' को धरती पर सैद्धान्तिक, प्रायोगिक और व्यावहारिक तीनों रूपों में प्रभावी रूप से समाज में पुनः स्थापित नहीं किया जायेगा तब तक धर्म–नाम सम्प्रदायों में सम्भाव का होना वैचारिक और भाषणीय व्याख्यान मात्र ही रहेगा । इस धरती पर समय–समय पर महापुरुषों, अंशावतारियों, रसूलों–पैगम्बरों, एन्जल्स–प्रॉफेट्स आदि उसी 'एक' सर्वोच्च शक्ति–सत्ता रूप खुदा–गॉड–भगवान द्वारा इस धरती पर भेजे जाते रहे हैं जो परिस्थिति के अनुसार जन समाज को उस सर्वोच्च शक्ति–सत्ता के तरफ मोड़ते रहे हैं । उन महापुरुषों द्वारा विभिन्न भाषाओं में एवं विभिन्न समयों में विभिन्न शब्दों से उस एक ही परमपुरुष रूप सर्वोच्च शक्ति–सत्ता को पुकारा जाता रहा है । परमात्मा–परमेश्वर–खुदा–गॉड– भगवान–सत्शीरी अकाल एक घ्कार–सत्पुरुष–परमपुरुष–अकाल पुरुष–बोधिसत्त्व–अरिहंत, यहोवा–अहूरमजदा–कुलमालिक आदि–आदि शब्दों से उसी परमब्रह्म रूप सर्वोच्च शक्ति–सत्ता के तरफ इंगित किया जाता है । वह एकमात्र 'एक' ही है । प्रॉफेट्स–पैगम्बर–अंशावतारी आदि उसी 'एक' का बनने और बने रहने की बातें समाज में रखते हैं किन्तु आज समाज उनके बताये गये विधानों को न अपनाकर उस 'एक' खुदा–गॉड–भगवान का न बनकर अपने अगुवाओं का मात्र बनकर अलग–अलग गुट बनाने में लगे हैं । अब यदि वे अपने अपने बड़प्पनबाजी में तनाव–टकराव पैदा करते है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और यदि सरकार भाई–चारा और शान्ति–व्यवस्था लाने में अपने सारे प्रयास को विफल हुआ पा रही हो तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है । यह स्थिति आज के विश्व समाज की हो गई है। ये सभी अपने–अपने बड़प्पन और श्रेष्ठत्त्व को उजागर करने में लगे हुए हैं। ईरान, बांग्लादेश, इजरायल आदि आदि देशों में जो तनाव, टकराव व संघर्ष या विघटन दिखाई दे रहा है सब ऐसे ही बडप्पनबाजी का ही तो परिणाम है।

बीडीओ ने रुकवाया अन्नपूर्णा भवन का निर्माण

सिंगाही – खीरी। विकास खंड निघासन की ग्राम पंचायत बंगलहा तकिया में अन्नपूर्णा भवन बनने को लेकर उपजे विवाद में शुक्रवार को बीडीओ ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और घोसियाना में बन रहे अन्नपूर्णा भवन के कार्य को रुकवा दिया और करदहिया में भवन को बनाने को लेकर लेखपाल के साथ भूमि का निरीक्षण किया।

गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों में कोटे का राशन वितरण अन्नपूर्णा भवन पर होना है। इसके लिए ग्राम पंचायतों में भवन बनाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत बंगलहा तकिया का अन्नपूर्णा भवन बनना शुरू तो इसी ग्राम पंचायत के मजरा घोसियाना में हुआ है। लेकिन करदहिया के सैकड़ों ग्रामीणों ने ब्लाक पहुंचकर इसके निर्माण का विरोध जताया था, साथ ही ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक शशांक वर्मा को ज्ञापन देकर आपत्ति दर्ज कराई थी । ग्रामीणों का कहना है कि करदहिया मजरे में लगभग 300 राशन कार्ड धारक निवास करते हैं, जबकि घोसियाना में केवल करीब 40 राशनकार्ड धारक हैं। जनसंख्या और आवश्यकता को देखते हुए अन्नपूर्णा भवन का निर्माण करदहिया में किया जाना अधिक उचित होगा। इसके बाद बीडीओ जयेश कुमार सिंह ने ग्राम पंचायत अधिकारी को निर्देश देकर काम रुकवा दिया था। शुक्रवार को बीडीओ स्वयं लेखपाल के साथ ग्राम पंचायत पहुंचे और घोसियाना में बन रहे भवन का निरीक्षण कर करदहिया पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। बीडीओ ने बताया कि लेखपाल के साथ करदहिया में जगह का निरीक्षण करने के लिए गए थे अगर राजस्व विभाग की ओर से हमें जमीन उपलब्ध हो जाती है तो अन्नपूर्णा भवन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घोसियाना में बन रहे अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कार्य अभी रुका हुआ है।

घोसियाना रोड पर सीडीओ का सख्त एक्शन, अतिक्रमण हटाने और नाली निर्माण पर खास फोकस

लखीमपुर खीरी, 16 जनवरी। घोसियाना की वास्तविक स्थिति और अतिक्रमण हटाने की शुक्रवार को अचानक मौके पर पहुंचे। निरीक्षण और निर्माण में बाधा बने अतिक्रमणों को देखा और कार्य पर विशेष फोकस रखने और इसे तेजी के साथ पूरा कराने के निर्देश भी जारी किए।

सीडीओ ने अधिशासी अभियंता (विद्युत) को भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।अधि रफ्तार देते हुए तय समय–सीमा के भीतर उच्च आमजन को जल्द राहत मिल सके। उन्होंने से समीक्षा करते हुए जरूरी सुधार के निर्देश भी स्थिति पूछी और समन्वय बनाकर काम करने भी संवाद करते हुए अपील की कि वे स्वेच्छा करें। सड़क निर्माण पूरा होते ही क्षेत्र की तस्वीर बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। निरीक्षण

रोड पर चल रहे सड़क और नाली निर्माण कार्य प्रगति जानने के लिए सीडीओ अभिषेक कुमार के दौरान उन्होंने सड़क के बीच खड़े विद्युत पोल तुरंत हटाने के निर्देश दिए। साथ ही नाली निर्माण साथ निर्धारित समय–सीमा में उच्च गुणवत्ता के

साफ शब्दों में कहा कि पोल शिफ्टिंग में किसी ाकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए, ताकि सड़क और नाली निर्माण की प्रगति की बारीकी दिए।सीडीओ ने मौजूद अधिकारियों से कार्य की पर जोर दिया। सीडीओ ने स्थानीय नागरिकों से से अतिक्रमण हटाकर प्रशासन का सहयोग बदलेगी और लोगों को सुगम, सुरक्षित और के समय एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह, पीडी (डीआरडीए) सोमनाथ चौरसिया, अधिशासी अभियंता (विद्युत) शैलेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

ट्रेंच विधि से करें बुवाई - डा पीके कपिल एडी

(हरिशंकर मिश्रध्शाजिफ हुसैन)

गोला गोकर्णनाथ खीरी। बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड चीनी मिल गोला के मिल गेट क्षेत्र के ग्राम भल्लिया बुजुर्ग में बसंतकालीन गन्ना बुआई अभियान के तहत एक कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान शाहजहाँपुर के सहायक निदेशक व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ पी के कपिल,ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक आशुतोष मधुकर,चीनी मिल के वरिष्ठ महा प्रबन्धक गन्ना पी एस चतुर्वेदी एवं मिल पारिक्षेत्र के लगभग 156 कृषकों ने भाग लिया। गन्ना संस्थान के सहायक निदेशक प्रवीण कुमार कपिल ने बसंतकालीन गन्ना उत्पादन तकनीक एवं गन्ना पेड़ी प्रबंधन, गन्ने में खाद एवं उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, गन्ने की स्वीकृत किस्मों एवं गन्ना बीज बदलाव, रिंग पिट बुवाई एवं गन्ना फसल सुरक्षा प्रबन्धन आदि पर प्रकाश डाला। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक गोला ने विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा उनमे देय अनुदान के बारे में तथा बसंत कालीन बुवाई में ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें, प्रजातियों,ड्रिप सिंचाई महिला स्वयं सहायता समूह से उत्पादित सीडलिंग के लगाने के लाभ बताये,साथ ही फार्म मशीनरी बैंक में उपलब्ध यंत्रों के सदुपयोग किफायती दरों में किराये पर ले जाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने तथा समिति द्वारा दी जाने वाली नैनो यूरिया तथा अन्य दवाइयां आदि के बारे में विस्तार से बताया।इसी क्रम में वरिष्ठ महा प्रबन्धक गन्ना ने कृषकों से अपील की कि अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए उन्नतशील गन्ना प्रजातियों जैसे को० 0118, को० 15023, कोशा० 13235, कोलख०14201 तथा जल भराव वाले क्षेत्रो के लिए को० 98014 एवं कोलख 94184 का चयन कर ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई करे । उन्होंने बताया कि गन्ने के ऊपरी एक–तिहाई हिस्से का जमाव अच्छा होता है, इसलिए ऊपरी एक तिहाई हिस्से को बीज में प्रयोग करके शेष भाग को मिल में आपूर्ति कर दें। तथा पेड़ी गन्ने की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए गन्ना कटाई के तुरन्त बाद सिचाई करके 75 किग्रा० यूरिया प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करे। साथ ही उन्होंने बताया कि चीनी मिल द्वारा कृषकों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है तथा मृदा उपचार हेतु ट्राइकोडर्मा व बीज उपचार हेतु फफूंदीनाशक थायोफिनेट मिथाइल भी मिल द्वारा कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराई जा रही है और ये भी बताया कि अपना बेसिक कोटा मजबूत बनाए रखने के लिए सारा गन्ना मिल को ही आपूर्ति करें। इस मौके पर सहायक महा प्रबन्धक गन्ना ओ डी शर्मा,प्रबन्धक गन्ना सत्येन्द्र कुमार मिश्र, वरिष्ठ गन्ना अधिकारी रामेश्वर दुबे, इंद्रपाल सिंह यादव, सहायक अधिकारी राहुल यादव, प्रगतिशील कृषक रामचन्द्र, राजकुमार, रामनरेश,रामकुमार पाण्डे, सराकतद्दीन,मो सलीम,मारूफ,बरकत अली सहित गन्ना समिति के गन्ना पर्यवेक्षक व चीनी मिल के मोटिवेटरध्कामदार सहित सैकड़ों कृषक उपस्थित रहे।

अब चलेगा स्कूली वाहनों एवं अनधिकृत पार्किंग के खिलाफ अभियान

लखीमपुर खीरी । सड़क सुरक्षा माह के सत्रवें दिन जिले की सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने स्कूल वाहनों व अवैध पार्किंग में खड़ी वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया तथा सदर के प्रमुख स्कूल अजमानी इंटरनेशनल स्कूल,लखनऊ पब्लिक स्कूल एवं जयपुरिया स्कूल में जाकर 98 वाहनों को चेक किया गया जिसमें लगभग सभी वाहन की फिटनेस एवं परमिट सही पाए गए है तथा अनफिट वाहन के विरुद्ध नोटिस दिया गया कि बिना फिटनेस के उक्त वाहन का संचालन न किया जाए। एवं स्कूल के वाहन चालकों को निर्देशित किया गया कि सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त मानकों को पूर्ण कर ही वाहन का संचालन संपन्न करेंगे।उक्त के अतिरिक्त शांति भूषण पाण्डेय एआरटीओ प्रवर्तन ओवरलोड और गन्ना परिवहन में प्रयुक्त ओवरहाइट वाहनों पर शिकंजा कसा। एआरटीओ शांति भूषण पांडे ने अभियान चलाकर गन्ने में संचालित ओवर हाइट वाहन के विरुद्ध बंद की कार्यवाही भी की। तत्पश्चात वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए पेम्प्लेट्स भी वितरित किए गए तथा आम जनमानस से अपील भी की गई कि सड़क सुक्षा नियमों का पालन करें।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 : मतदाता सूची में नाम जाचें, 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराएं

लखीमपुर खीरी,16 जनवरी। मतदाता सूची को दुरुस्त और पारदर्शी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण –2026 कार्यक्रम को रफ्तार दे दी है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 कार्यक्रम के अन्तर्गत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने करने की अवधि 06 फरवरी 2026 तक है।मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर आयोग ने चार विशेष अभियान दिवस तय किए हैं। 17 और 18 जनवरी तथा 31 जनवरी और 1 फरवरी को जिले के सभी पदाभिहित स्थलों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन तिथियों पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर आवश्यक स्टाफ की तैनाती के साथ पदाभिहित अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।विशेष अभियान के दौरान हर बूथ पर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, जहां मतदाताओं को फार्म भरने में मदद दी जाएगी। फार्म–6, 6ए, 7 और 8 (घोषणा–पत्र सहित) पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहेंगे। प्राप्त सभी दावे और आपत्तियों का सुव्यवस्थित अभिलेखीकरण किया जाएगा, ताकि निरीक्षण के समय तुरंत उपलब्ध कराया जा सके। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को भी अभियान की तिथियों से अवगत कराकर सहयोग लिया जाएगा।अभियान को प्रभावी बनाने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं पदाभिहित स्थलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण कार्यक्रम इस तरह बनाया जाएगा कि कोई भी बूथ छूटने न पाए। इसके तहत 18 जनवरी को सुबह 10रू30 बजे से शाम 4रू30 बजे तक सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने–अपने बूथ पर उपस्थित रहकर आलेख्य निर्वाचक नामावली का वाचन करेंगे। साथ ही बीएलओ के पास अप्राप्त (न्दबवससमबजंइसम), अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृतक और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी उपलब्ध रहेगी, जिससे मतदाताओं को सही जानकारी दी जा सके।निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं 5 बूथों और उप जिला निर्वाचन अधिकारी 10 बूथों का निरीक्षण करेंगे। वहीं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक अधिकारी अपने विधानसभा क्षेत्र के 10 प्रतिशत पोलिंग स्टेशनों का भ्रमण करेंगे।जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने मतदाताओं से अपील की है कि वे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अवजमते.मबप.हवअ.पद और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर अपना या अपने परिवार के सदस्यों का नाम जांचें और जरूरत पड़ने पर निर्धारित फार्मों के माध्यम से आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

तन मन से एसआईआर पर लग जाए कार्यकर्ता, सुनील सिंह

गोला गोकर्णनाथ खीरी।शुक्रवार 16 जनवरी को नगर पालिका परिषद गोला के सभागार में भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर खीरी की आवश्यक बैठक भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक का शुभारंभ पार्टी के पुरोधा पं० दीनदयाल उपाध्याय,डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित कर अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान से की गई।इसके उपरांत जिला महामंत्री रामजी मौर्य ने एसआईआर पर मण्डल अध्यक्षों से फार्म 06 ,07 तथा 08 के द्वारा नये मतदाता बनाने, संशोधन तथा गलत मतदाताओं के नाम हटाने की समीक्षा रिपोर्ट ली। जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि,ष 2003 के बाद एसआईआर हो रही है यह मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य है इसलिए तन मन धन से एसआईआर पर लग जाइए।जिला उपाध्यक्षध्चेयरमैन नगर पालिका परिषद गोला विजय शुक्ला रिंकू ने कहा,ष दस दिन का समय ही शेष बचा है , सब काम छोड़कर नये मतदाता बनाना होगा।

जिला महामंत्री एवं अभियान संयोजक ज्योतिर्मय बरतरिया ने कहा कि,ष कार्यकर्ताओं को मनोयोग से एसआईआर के ड्राफ्टेड वोटर तथा नये मतदाताओं के फार्म भरवाने होंगे। कोई भी पात्र व्यक्ति रहना नही चाहिए।बैठक में भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामू पाण्डेय, जिला महामंत्री आशू मिश्रा,विनोद लोधी, जिला उपाध्यक्ष विनोद वर्मा, संतोष कुमारी, जिला मंत्री उमेश शुक्ला, उमा राज,बृजेश सिंह, राकेश अर्कवंशी,दुर्गेश नंदन पाण्डेय, विनय गुप्ता,पूर्व जिला महामंत्री अनुराग मिश्रा, अशोक अवस्थी, रामजी रस्तोगी,बालमुकुंद दीक्षित, संदीप मौर्य ,रामानुज मिश्रा, धीरेन्द्र सिंह, दीपक मिश्रा, नीरज सिंह चौहान, अरविन्द गुप्ता ,धीरज बाजपेयी ,सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कैम्प में पंजीकृत पेंशन, राशनकार्ड तथा अन्य आवेदनों का यथाशीघ्र निस्तारण होगा- विजय शुक्ला रिंकू

अंतिम दिन 406 लोगों ने कराया पंजीकरण

गोला गोकर्णनाथ खीरी। शुक्रवार 16 जनवरी को नगर पालिका परिषद गोला के तत्वावधान में कैम्प के अंतिम दिवस कुल 406 रजिस्ट्रेशन हुए। नगर पालिका प्रांगण में विभिन्न समस्याओं को लेकर लोगों नें रजिस्ट्रेशन कराए जिसमें वृद्धावस्था के 39 रजिस्ट्रेशन हुए जिसमें 31लोगों की पेंशन रुकी हुई थी 08 नये रजिस्ट्रेशन किए गए ,राशनकार्ड के 221 लोगों ने कैम्प में पंजीकरण कराया जिसमें 209 कार्डधारक थें जिनको यूनिट बढवानी थी शेष 12 नये कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन हुए ,विद्युत विभाग के 03 पंजीकरण हुए 01स्मार्ट मीटर की रीडिंग के रजिस्ट्रेशन थे तथा 02 बिल बढोत्तरी के लिए पंजीकरण हुए,दिव्यांग पेंशन के 02,विधवा पेंशन के 07 पंजीकरण हुए। नगर पालिका परिषद से सम्बंधित 33 पंजीकरण हुए जो जन्मप्रमाण के थे ।साथ ही नये मतदाता बनने के भी 103 फार्म वितरित किए गए।नगर पालिका आपके द्वार अभियान में उपस्थित आमजन को सम्बोधित करते हुए पालिकाध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने कहा कि,ष अभी तक केकैम्प में पंजीकृत सभी की समस्याओं का शतप्रतिशत निस्तारण किया जाएगा।इस अवसर पर सभासद नानक चन्द्र वर्मा, इजरान ,राजेश पटेल, धर्मेन्द्र तिवारी टीटू,हरिओम वर्मा,वरिष्ठ लिपिक अमित श्रीवास्तव, एस आई संदीप वर्मा,जेई अनिल कुमार यादव, जेई आदर्श मिश्रा, श्रवण कुमार मिश्रा, अंकित गुप्ता,अशोक मिश्रा,विजय कुमार, प्रदीप कुमार,अनुज अवस्थी,विमलेश वर्मा,जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से विकास वर्मा , जिला समाज कल्याण विभाग अंकित सिंह,खाद्य एवं रसद विभाग से अजय कुमार,आनंद कुमार ,प्रोवेशन कार्यालय लखीमपुर से रामकुमार वर्मा, नगर मंत्री धीरज बाजपेयी, नगर महामंत्री राजेश राठौर, शत्रोहन मिश्रा आदि मौजूद रहे।

लखनऊ के होटल हयात में ठहरे बजाज फाइनेंस के सीनियर मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

लखनऊ। शुक्रवार 16 जनवरी 2026 को प्रातः लगभग 10रू30 बजे थाना विभूतिखण्ड पुलिस को होटल हयात से सूचना मिली कि होटल में ठहरे एक युवक अपने कमरे में अचेत अवस्था में पाए गए हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच शुरू की गई।पुलिस के अनुसार युवक अपने कमरे में बेसुध अवस्था में मिले, जिसके बाद उन्हें तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जांच में मृतक की पहचान मोहम्मद फहिम्मुद्दीन जाहिद पुत्र नजीरुद्दीन मोहम्मद, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी मीरा रोड ईस्ट, शान्तिनगर सेक्टर–9, ठाणे (महाराष्ट्र) के रूप में हुई है। मृतक बजाज फाइनेंस कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और कार्यालयी कार्य से लखनऊ आए थे। वे 14 जनवरी 2026 से होटल हयात में ठहरे हुए थे।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। पोस्टमार्टम की अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार कराई जाएगी। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है, जो कर्नाटक से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। परिजनों के आगमन के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल मामले में आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया प्रचलित है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय में श्रीराम प्रतिमा का किया अनावरण

भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा संगोष्ठी में हुई शामिल

अयोध्या।उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती

आनंदीबेन पटेल आज महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या में आयोजित भगवान श्रीराम की 35 फीट ऊँची भव्य प्रतिमा के अनावरण समारोह एवं भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा संगोष्ठी कार्यक्रम में सम्मिलित हुईं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम की यह दिव्य प्रतिमा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण होने के साथ–साथ सत्य, धर्म, करुणा और कर्तव्य जैसे मानव जीवन के सर्वोच्च आदर्शों की जीवंत अभिव्यक्ति है।राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान श्रीराम भारत की सांस्कृतिक चेतना के केंद्र हैं। उनका जीवन सुशासन, सामाजिक समरसता और नैतिक नेतृत्व के कालातीत आदर्श प्रस्तुत करता है। प्रभु श्रीराम यह संदेश देते हैं कि सत्ता सेवा का माध्यम हो, शक्ति संयम से संचालित हो और निर्णय लोकमंगल से प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि आधुनिक विकास की दौड़ में मानवीय मूल्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और बिना नैतिकता व करुणा के वास्तविक विकास संभव नहीं है।कार्यक्रम के दौरान डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या एवं महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या के मध्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यपाल ने इस पहल को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह अकादमिक साझेदारी शैक्षणिक सहयोग, संयुक्त शोध, अनुसंाान और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को सुदृढ़ करेगी तथा अयोध्या को ज्ञान एवं संस्कृति के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी।भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्ति नहीं, बल्कि जीवन निर्माण रहा है। सा विद्या या विमुक्तये की भावना के अनुरूप भारतीय शिक्षा चरित्र निर्माण, विवेक जागरण और करुणा के संस्कार देती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा एक–दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं।राज्यपाल ने महर्षि महेश योगी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका मानना था कि स्थायी शांति का मार्ग व्यक्ति की आंतरिक चेतना से होकर गुजरता है। चेतना–आधारित शिक्षा की अवधारणा आज के तनावग्रस्त वैश्विक परिवेश में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक विषयों से जोड़ते हुए समग्र शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।उन्होंने अयोध्या को रामराज्य के आदर्शों का शाश्वत प्रतीक बताते हुए कहा कि यह नगरी न्याय, करुणा, नैतिक शासन और सामाजिक समरसता का संदेश देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान नवभारत के निर्माण की मजबूत नींव हैं।राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथों से प्रेरणा लेकर डिजिटल, रचनात्मक और तकनीकी माध्यमों से भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को वैश्विक मंच पर स्थापित करें।इस अवसर पर अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, अयोध्या विधानसभा के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अजय प्रकाश श्रीवास्तव, कुलपति प्रो. बी.पी. सिंह सहित अनेक गणमान्यजन, शिक्षकगण एवं छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

थाने में युवकों का हंगामा, मारपीट कर मोबाइल छीनने का आरोप

प्रयागराज। अतरसुइया थाने में गुरुवार को उस समय अफरा–तफरी मच गई, जब थाने पहुंचे तीन युवकों ने थाने में तैनात ड्राइवर संजय पर गंभीर आरोप लगाए। युवकों का आरोप है कि सादे कपड़ों में मौजूद आरोपी ड्राइवर ने उनके एक साथी के साथ मारपीट की और मोबाइल फोन छीन लिया। घटना को लेकर थाने परिसर में जमकर हंगामा हुआ।

आरोप लगाने वाले युवकों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया है, जिसमें आरोपी ड्राइवर संजय से उनकी नोकझोंक होती साफ दिखाई दे रही है। वीडियो में मौके पर थाना प्रभारी राममूर्ति यादव समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। युवकों का कहना था कि वे थाने में एक पीड़ित का मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन पिछले कई दिनों से थाने के चक्कर कटवाए जा रहे थे। इसी शिकायत को लेकर वे थाना प्रभारी से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद ड्राइवर संजय से कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई और मोबाइल छीन लिया गया।इस पूरे मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर संजय की अतरसुइया थाने में यह दोबारा पोस्टिंग है,

महत्वपूर्ण है साहित्य का सामाजिक उद्देश्य : रघुवंशमणि

अयोध्या। जनवादी लेखक संघ, फैध्जाबाद की मासिक गोष्ठी एवं तदनंतर रचना–पाठ का कार्यक्रम गुप्तार घाट स्थित उद्यान परिसर में आयोजित किया गया। रचना–पाठ में साथी संगठनों के रचनाकारों सहित अन्य कई लेखकों एवं साहित्यप्रेमियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर आलोचक डॉ. रघुवंशमणि ने हिंदी की महत्वपूर्ण पत्रिका 'पहल' के सम्पादक कथाकार ज्ञानरंजन को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से ऐसे कई रचनाकारों को सामने लाने का काम किया जो आज साहित्य में अत्यंत महत्व रखते हैं। पहल में छपने का अर्थ होता था कि समूचा हिंदी समाज आपको पढ़ और जान रहा है। उन्होंने कहा कि सम्पादक के रूप में ज्ञानरंजन की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने साहित्य के सामाजिक उद्देश्य को सामने रखा। वे ऐसे सम्पादक थे जो हर छोटे–बड़े रचनाकार को बाकायदा पत्र लिखकर उत्तर देते थे। ज्ञानरंजन जी की दुनिया भर के लेखन के बारे में अद्भुत जानकारी थी, हिंदी समाज को उनसे और अधिक संवाद करने की जरूरत थी। वरिष्ठ कवि स्वप्निल श्रीवास्तव ने कवि विनोद कुमार शुक्ल से जुड़े हुए संस्मरणों को सुनाते हुए उनकी मशहूर कविता 'रायपुर सम्भाग' का जिक्र किया और बताया कि कैसे वे उसे सुनाते हुए अत्यंत भावुक हो गए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कई बार लेखन में प्रतिबद्धता का तत्व बहुत सामने से न दिखते हुए भी अन्तर्वस्तु में समाहित होता है। डॉ. विशाल श्रीवास्तव ने इन दोनों रचनाकारों के महत्व को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कई बार लेखक स्पष्ट तौर पर किसी वैचारिक संगठन का हिस्सा नहीं होता लेकिन उसके लेखन का समग्र प्रभाव अत्यंत प्रगतिशील होता है। उन्होंने प्रसिद्ध दलित लेखक–कवि डॉ. सी.बी. भारती की वैचारिक कविता 'यह कैसा लोकतंत्र' का पाठ उपस्थित प्रबुद्धजन के बीच किया। कार्यक्रम में हिंदी–अवधी के महत्वपूर्ण रचनाकार आशाराम 'जागरथ' सहित जलेस के सदस्यों जे.पी. श्रीवास्तव, डॉ. नीरज सिन्हा 'नीर', अखिलेश सिंह, पूजा श्रीवास्तव, राजीव श्रीवास्तव, रवीन्द्र कबीर, शिवांगी, विजय श्रीवास्तव तथा ओम प्रकाश रोशन ने अपनी रचनाएं सुनाईं। सांगठनिक सत्र की अध्यक्षता इकाई के अध्यक्ष मो. जफर तथा पूरे कार्यक्रम का संचालन कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारी सचिव मुजम्मिल फिदा द्वारा किया गया। सत्यभान सिंह 'जनवादी' ने कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस तरह के कार्यक्रमों की निरंतरता पर जोर दिया। इससे पहले जनवादी लेखक संघ इकाई की पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी और सदस्यता के नवीनीकरण, विगत आयोजनों की समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजनाओं के बारे में विचार किया गया। कार्यक्रम में बृजेश कुमार श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, साधना सिंह, दीपक, महावीर पाल, संदीप सिंह ,शालिनी सिंह,तिलक राज तिवारी,विनय पाठक,अजय बाबा,सिद्धार्थ आनंद सहित कई साहित्य–संस्कृति प्रेमी उपस्थित रहे।

टैक्सी चालक का अपहरण कर हत्या करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, लूटी कार व मोफलर बरामद

अयोध्या।पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में हुए अपहरण व हत्या के सनसनीखेज मामले का सफल अनावरण किए जाने की जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि टैक्सी चालक का गाड़ी सहित अपहरण कर हत्या करने और शव को छिपाने के मामले में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार, मृतक की चेन–अंगूठी तथा हत्या में प्रयुक्त मोफलर बरामद की गई है।एसएसपी ने बताया कि शासन के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी अयोध्या के निकट पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई। दिनांक 15 जनवरी 2026 को अवध बिहारी का पुरवा एयरपोर्ट पक्के नाले की पुलिया के पास से चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी थाना कोतवाली अयोध्या में पंजीकृत मुकदमा संख्या 18ध्25 के तहत की गई। घटना दिनांक 23 नवंबर 2024 को वादिनी ने थाने पर सूचना दी थी कि उसके पति अजीत गुप्ता टैक्सी लेकर बाहर गए थे और 21 नवंबर की रात फोन पर गोरखपुर जाने की बात कहने के बाद घर नहीं लौटे। इस संबंध में पहले गुमशुदगी दर्ज की गई, बाद में साक्ष्य सामने आने पर अपहरण व हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।जांच में एसओजी व सर्विलांस टीम की मदद से सामने आया कि अभियुक्तों ने योजनाबद्ध तरीके से अयोध्या से गोरखपुर जाने के लिए स्विफ्ट डिजायर कार बुक कराई। कैंपियरगंज (गोरखपुर) ले जाकर अजीत गुप्ता की गला कसकर हत्या कर दी गई। इसके बाद उनकी चेन, अंगूठी व कार लूट ली गई और शव को छिपाने की नीयत से बिहार के मुजफ्फरनगर जनपद के थाना सकरा क्षेत्र में फेंक दिया गया। घटना के बाद आरोपी अलग–अलग शहरों में मोबाइल व लोकेशन बदलकर छिपते रहे।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, ४० वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी २/३७६ रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ० प्र० से प्रकाशित।
सम्पादक
आरती पाण्डेय
eks-
9807059191- 9026560178
Email-
adbhutsamachar@gmail.com
adbhutsamachar@hotmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।